

## कानपुर जनपद में नगरीय वृद्धि एवं उसका पर्यावरण पर प्रभाव (एक भौगोलिक अध्ययन)

शिवा पटेल <sup>1</sup>, भूपेन्द्र यादव <sup>2</sup>, डॉ० अनुपमा सिंह <sup>3</sup>

<sup>1, 2</sup> शोध छात्र, भूगोल विभाग, डी०ए०वी० कॉलेज कानपुर (उ०प्र०)

<sup>3</sup>असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डी०ए०वी० कॉलेज कानपुर (उ०प्र०)

### सारांश—

पिछले कुछ वर्षों में कानपुर जनपद में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर शहरीकरण और नगरीय विस्तार हुआ है। भारतीय राज्यों में कानपुर जनपद अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। अत्यधिक नगरीकृत होने के नाते इसकी संस्कृति समस्त विश्व की संस्कृति को भी प्रभावित कर रही है। क्योंकि नगरीकरण को स्थानीय भूमि प्रयोग और समस्त भूमि के उपयोग परिवर्तन के सर्वाधिक प्रभावी कारणों में से एक माना जाता है कानपुर जनपद की आर्थिक विकास क्रियाविधि जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई; अप्रयोजित नगरीकरण, अत्यधिक जनसंख्या विस्तार, कृषिगत उपज की मांग, जनसांख्यिकीय भूमि उपयोग में परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि कारणों से कानपुर जनपद में पर्यावरणीय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में जनपद आर्थिक प्रतिस्पर्धा के चलते स्थानीय संसाधनों का अविवेकीपूर्ण उपयोग कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर की सामाजिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। प्रस्तुत रिसर्च पेपर जनपद के जनसंख्या विस्तार सम्बन्धी आँकड़ों और भूमि आवरण में परिवर्तन का संश्लेषण करके पर्यावरण पर नगरीकरण के स्थानीय प्रभावों का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है।

**मुख्य शब्द :** जनसांख्यिकीय परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, पर्यावरणीय अवनयन, भूक्षरण, सामाजिक दुष्प्रभाव।

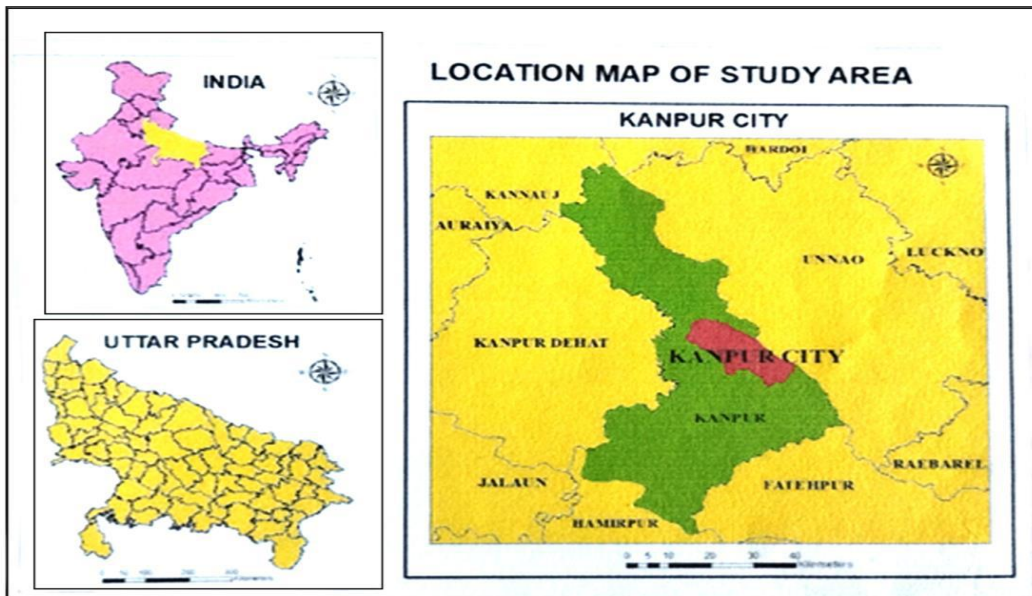
### प्रस्तावना :

ग्रामीण क्षेत्रों में चरम बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी, सांस्कृतिक टकराव, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पिछड़ापन, आधारभूत अवसंरचना विकास की कमी तथा शहरीकृत रोजगार की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के साधनों ने ग्रामीण जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित किया जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या का गाँव से नगरों की तरफ पलायन में वृद्धि हुई है। क्योंकि कहीं न कहीं शहरीकरण की गतिशीलता सकारात्मक आर्थिक विकास, अनुकूलित वातावरण ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है।

अत्यधिक नगरीकरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं से जुड़ा होता है सकारात्मक पहलुओं के अन्तर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, प्रशासनिक सुविधा, आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता, जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव इत्यादि कारणों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि नकारात्मक पहलुओं के अन्तर्गत शहरी जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक भूमि अवसंरचना पर दबाव, यातायात असुविधा, पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास एवं सामाजिक अपराध इत्यादि के विस्तार के चलते नगरीय जनसंख्या को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। विगत कुछ वर्षों में जनपद में अवसंरचना विकास की तीव्र वृद्धि दर एवं विस्तृत पैमाने पर जनपद की चतुर्दिश क्षेत्रीय एवं लम्बवत आर्थिक विस्तार गतिविधियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास गतिविधियों के कारण कानपुर जनपद में अनियोजित बस्ती प्रारूप एवं अनियोजित शहरी विकास, भूमि दबाव, वनों की कटाई, अविवेकीपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार, संघन जनसंख्या एवं भूमि अवसंरचना का क्षरण जैसी सुविधाओं के लिए जनपद के आंतरिक आवासों की आवश्यकता के रूप में समझा जाता है।

### अध्ययन क्षेत्र—

केन्द्रीय आर्थिक आंकड़ों के अनुसार कानपुर जनपद एक अत्यधिक शहरीकृत समूह के अन्तर्गत आता है जो अत्यधिक संघन जनसंख्या घनत्व को संसूचित करता है। कानपुर जनपद का क्षेत्रफल 403 वर्ग किमी<sup>0</sup> है, जो राज्य के मध्य-पश्चिम भाग में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाय तो कानपुर जनपद में पर्यावरणीय ह्रास विनाशकारी प्रभाव, अनियोजित नगरीकरण, शहरी आबादी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के प्रभावों को शामिल किया जाता है। कानपुर जनपद राज्य के अन्तर्गत आने वाले वृहद औद्योगिक नगरों में से एक है। कानपुर नगर का भौगोलिक विस्तार 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है।



कानपुर जनपद की केन्द्रीय जनगणना (2011) के अनुसार जनसंख्या घनत्व 4572951 है।

### उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन जनपद के निम्न विश्लेषणों पर आधारित होगा।

- 1— कानपुर जनपद के नगरीय अवसंरचना विकास का सूक्ष्म विश्लेषण करना।
- 2— आर्थिक प्रतिस्पर्धा के चलते जनपद की पर्यावरणीय समस्याओं का आँकलन करना।
- 3— नगरीय अवसंरचना विकास एवं पर्यावरणीय समस्याओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना एवं सतत पर्यावरणीय विकास का अध्ययन करना।

### शोध विधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन अत्यधिक नगरीकरण के कारण सामाजिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन पर आधारित है। जिसका विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक आँकड़ों के उचित उपयोग के साथ-साथ द्वितीयक आँकड़ों का भी उपयोग किया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन को अत्यधिक तार्किक बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों का भी उपयोग किया जायेगा।

### परिणाम एवं परिचर्चा :

2011 की केन्द्रीय जनगणना के अनुसार कानपुर जनपद का शहरीकरण प्रतिशत 65.8% था जिसकी लगभग एक तिहाई जनसंख्या वर्तमान में जनपद के शहरी विस्तार सीमा से विलग निवास करती है। कानपुर जनपद का नगरीकरण का स्तर राष्ट्रीय स्तर से लगभग दोगुना ज्यादा है जो उत्तर भारतीय जनपदों में सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्रों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

#### 1— भूमि अवनयन में वृद्धि :

स्थानीय लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दिन-प्रति दिन नये औद्योगिक संस्थानों एवं उत्पादन कारकों की स्थापना हो रही है, जो कहीं न कहीं पर्यावरणीय पहलुओं पर दबाव डाल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय संसाधनों का ह्रास हो रहा है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से पर्यावरणीय ह्रास, जल में कमी, खाद्य असुरक्षा एवं विनिर्माण गतिविधियों ने भूमि अवनयन को बढ़ावा दिया है।

#### 2— प्राकृतिक संसाधनों के प्रदूषण का खतरनाक स्तर :

स्थानीय भूमि में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। जिसमें कम भूमि क्षेत्र में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करना ही कृषक का प्रथम लक्ष्य बन चुका है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में

प्रति एकड़ भूमि से अत्यधिक उत्पादन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जहरीले कीटनाशकों का बेतहाशा प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।

### 3— पर्यावरणीय ह्रास के कारण नदियों के गुणवत्ता में ह्रास :

आर्थिक विकास के चलते जनपद के चतुर्दिश क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के स्थापना की होड़ सी लगी रहती है, जिसके कारण जनपद का आर्थिक विकास और विस्तार तो सुनिश्चित होता है, परन्तु व विकास पर्यावरण की कीमतों को चकाकर ही होता है। जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भूमि के उपजाऊपन में कमी का आना, भूमिगत जल संसाधनों का नीचे की तरफ शिफ्ट करना एवं विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय ह्रास को उत्पन्न करना है। कानपुर नगर में अनेक प्रकार के औद्योगिक कारखानों के व्यर्थ जल प्रवाह बढ़ती समस्याओं और अधिक उपयोग के कारण नदियों की गुणवत्ता का क्षय हो रहा है।

### 4— वन और पर्यावरणीय विविधता का अवनयन :

स्थानीय आवश्यकताओं ने जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द भूमि, वनों का कटाई, स्थानान्तरित कृषि पद्धति, अनियोजित रूप से सांस्कृतिक संसाधनों का दोहन, बस्तियों का निर्माण इत्यादि कारणों ने जैव-विविधता को प्रभावित किया है। पर्यावरणीय विविधता का ह्रास पारिस्थितिक तंत्र के आधार को घटा रहा है जिससे यह खाद्य श्रृंखला एवं जीव-जन्तुओं को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। स्थानीय संसाधनों का अनियोजित रूपसे संग्रहण पारिस्थितिक तंत्र को वृहद मात्रा में नष्ट कर रहा है।

### 5— अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण :

आर्थिक गतिविधियों में जैसे-चमड़ा उद्योग, बेकरी उद्योग, जल विद्युत उत्पादन, उर्वरक उद्योग, रासायन उद्योग, जैसे उत्पादन कारकों ने नगरीय पर्यावरण को वृहद पैमाने पर दूषित किया है। जनपद में क्षेत्रीय स्तर पर अवस्थित औद्योगिक उत्पादनों के द्वारा बचे हुये शेष व्यर्थ उप-उत्पादों को बिना संशोधित किये सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे नदियां पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ, मृदा भी स्थानीय स्तर पर प्रदूषित हो रही है। एवं बंजर भूमि में वृद्धि का कारण बन रही है।

### 6— शहरीकरण का बदलता स्वरूप :

ग्रामीण जनसंख्या के शहरों में अत्यधिक प्रवास के कारण बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के बस्तियों का अनियोजित विस्तार, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है, जैसे-स्वास्थ्यकर आवास की कमी, गुणवत्ता पूर्ण पेयजल एवं पर्यावरण इत्यादि का अभाव।

शहरों की आंतरिक जनसंख्या के दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के आवश्यक उत्पादक कारकों की स्थापना शहर के क्षेत्रीय एवं लम्बवत विस्तार को बढ़ाता है, जिसके कारण शहरी कूड़ा-कचरा के अवशेषों में वृद्धि होती है, जो कि पर्यावरणीय गुणवत्ता के ह्रास का कारण बनती है।

**सुझाव :**

**1— पर्यावरण कानून का पालन :**

समय-समय पर राज्य सरकारों के द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए तथा सतत विकास के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय कानून बनाने का सराहनीय कदम भी उठाना पड़ता है। जिसके क्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ही अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम (1980), केन्द्रीय जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम (1974) इत्यादि। केन्द्र सरकार द्वारा पारित पर्यावरणीय कानूनों का ईमानदारी से पालन करके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) को सुचारु रूप से सफल बनाया जा सकता है जिसके चलते पर्यावरणीय गुणवत्ता में ह्रास को कम किया जा सकता है।

**2— सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना :**

टिकाऊ भविष्योन्मुख विकास के लिए सतत प्रविधियों का प्रयोग सुनिश्चित करना वर्तमान मांग है जिसके आधार पर ही हम सतत विकास के सपने को साकार कर सकते हैं। शहरों के अन्तर्गत सतत विकास के लिए बस्तियों का वैज्ञानिक बसाव, जल प्रवाह की सुचारु रूप में व्यवस्था जो कि स्थानीय अधिवासों को प्रभावित न करें। शहरों के अन्तर्गत बेहतर अवसंरचना सुविधा, टिकाऊ पर्यावरणीय विकास कार्य एवं अनेक प्रकार के पुनःचक्रणीय प्रविधियों की स्थापना करके शहरों की आंतरिक अपशिष्टों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित कर सकते हैं।

शहरों के अन्तर्गत सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करके सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**3— अनियंत्रित जनसंख्या पर रोक :**

तीव्र गति से बढ़ता शहरीकरण अपने चकाचौंध से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक आकर्षण सम्मिलित है, शहरों के आंतरिक व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित आधारभूत अवसंरचना, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की सुलभतापूर्ण उपस्थिति, जैसे कारकों ने ग्रामीण पलायन को बढ़ाया है, जिसमें नगरीय जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पर्यावरणीय गुणवत्ता में ह्रास का सीधा सम्बन्ध अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ है, जिसमें अत्यधिक जनसंख्या का पर्यावरण पर दबाव विभिन्न रूपों में व्यापक स्तर पर परिलक्षित होता है।

**4— सामाजिक जागरूकता के लिए प्रचार—प्रसार :**

शहरीकरण के कारण बदलते पर्यावरणीय स्वरूप में सबसे अधिक दुष्प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है, अतः इस दुष्प्रभाव को कमतर करने के लिए समय—समय पर पर्यावरण को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जाना ही सबसे बेहतर कदम होगा। शहरीकरण में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय ह्रास के फलस्वरूप सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न तरह के समाचार पत्रों, सम्मेलनों एवं नाट्य सभा का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए।

**5— पुनर्चक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना :**

बढ़ते शहरीकरण के द्वारा उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय ह्रास को कम करने के लिए शहरों के चतुर्दिश हरित पेटी का निर्माण करना तथा शहरों के अन्दर हरित भवनों के डिजाइन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ सार्वजनिक पार्कों का निर्माण करके शहरीकरण के द्वारा पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। शहरी अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति के लिए शहरों के अंदर विभिन्न स्थानों पर आवश्यक मात्रा में पुनर्चक्रिय अपशिष्ट प्रबंधनों की स्थापना करना एवं यथा आवश्यक स्वच्छ उत्पादन प्रक्रमों की स्थापना करना।

**6— हरित विकास को बढ़ावा देना :**

शहरीकरण में वृद्धि के फलस्वरूप लोगों को अपने स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पर्यावरण के गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है, जिसका उचित मूल्य उन्हें अपने स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर समय—समय पर करना पड़ता है, क्योंकि शहरी पर्यावरण अत्यधिक नगरीय वृद्धि के चलते ज्यादातर मात्रा में दूषित हो चुकी होती है। अतः शहरों में दूषित पेयजल, प्रदूषित वायु, भूमिगत संसाधनों का अभाव इत्यादि जैसी समस्याएँ स्थानीय लोगों के समझ उत्पन्न होती हैं। शहरी हरित विकास को बढ़ावा देने तथा सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए वनारोपण अभियान जैसे जनजागरूकता अभियान को चलाया जाना चाहिए।

**7— नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना :**

नियोजित शहरी विकास करने को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्र विकास योजनाओं का निर्माण करना एवं उसको सुचारु रूप से स्थानीय स्तर पर लागू करना। जैसे— चण्डीगढ़ शहर का मास्टर प्लान, जमशेदपुर का मास्टर प्लान, दिल्ली का नियोजित विकास मॉडल इत्यादि जैसे कदमों को अपनाना चाहिए।

**निष्कर्ष :**

तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय ह्रास का कारण बन रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे— भूमिक्षरण, वन विनाश, संसाधनों का दोहन द्वारा उत्पन्न हो रही है। अतः

जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता में संतुलन स्थापित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है। जिसके लिए शहरी विकास के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को एक साथ लेकर चलना ही बेहतर उपाय हो सकता है।

**संदर्भ :**

- 1— अग्रवाल, अनिल (1995), सतत विकास क्या है? प्रशासनिक पृष्ठ XI अप्रैल-जून 1995
- 2— इराक भरुचा (2006), पर्यावरणीय अध्ययन पर एक लेख, विश्वविद्यालय प्रेस, ENVIS केन्द्र
- 3— बंसल, एस0सी0 'नगरीय भूगोल' मिनाक्षी प्रकाशन मेरठ
- 4— केन्द्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2013), वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार
- 5— भगत, आर0बी0 (1997) 'ग्रीन हाउस गैस वृद्धि के सम्बन्ध में जनसंख्या और पर्यावरण में सम्बंध क्षेत्रीय विज्ञान पर भारतीय पत्रिका
- 6— भारतीय जनगणना 2011
- 7— जिला सांख्यिकीय रिपोर्ट-2019